



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 204]

नई विलो, सोमवार, मई 24, 1982/JYAIESTHA 3, 1904

No. 204]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 1982/JYAIESTHA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(ओद्योगिक विकास विभाग)

आवेदन  
नई विलो, 24 मई, 1982

का० आ० 344(अ)/18 कक्ष/आई० डी० आ० ८०/८१—भारत  
मरकार के उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विकास विभाग) के आवेदन सं० का  
आ० 826(प्र) 18 कक्ष आई० डी० आ० ८०/८६ तारीख 25 नवम्बर,  
1976 द्वारा [जिसे इसके पश्चात् उक्त आवेदन कहा गया है, उद्योग  
(विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951] (1951 का 65) की धारा  
18 कक्ष की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रधीन मैसर्स पुलगांव काटन  
मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक ओद्योगिक उपकरण का पूर्ण प्रबंध 24  
नवम्बर, 1981 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी  
सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया था और उक्त ओद्योगिक उपकरण का प्रबंध  
ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटायल कारपोरेशन को प्राधिकृत  
किया गया था;

और भारत मरकार के उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विभाग)  
के आवेदन सं० का० आ० 825(प्र)/18 कक्ष/आई० डी० आ० ८०/८१  
तारीख 24 नवम्बर, 1981 द्वारा उक्त आवेदन को प्रबंध 24 मई, 1982  
तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बड़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लंकाहित में ऐसा करना  
समीक्षीय है कि उक्त ओद्योगिक उपकरण न प्रबंध 24 अगस्त, 1982

तक तीन मास की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटायल कारपोरेशन के प्रधीन बना रहे;

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक्ष की उपधारा (2)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियेश देता है कि उक्त  
आवेदन 24 अगस्त, 1982 तक, तीन मास की और अवधि के लिए,  
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 3/17/75-सी०य०सी०एस०]

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
(Department of Industrial Development)  
ORDERS

New Delhi, the 24th May, 1982

S.O. 344(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18AA/IDRA/76, dated the 25th November, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1981 and the Maharashtra State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop-

ment) No. S.O. 825(E)/18AA/IDRA/81, dated the 24th November, 1981, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 24th May, 1982;

An, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Maharashtra State Textile Corporation for a further period of three months upto and inclusive of the 24th August, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of the 24th August, 1982.

[File No. 3/17/75-CUS]

का० आ० 345(अ)/18 अव/आईडीआरए—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 अव धारा (1) के छण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने पर, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (श्रीयोगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का आ० 826(अ)/18 अव/आईडीआरए/76 तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रावेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की सारी बांधकानों से ठीक पूर्ण प्रवृत्त सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हस्तान्तरण पत्रों, करारों, अवस्थापत्रों, पंचाटों, स्थायी आवेदनों या अन्य लिखतों (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकाब प्रत्यय सीमा के अधीन परावेय रकम के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिशायितों को भी नकाब प्रत्यय सेवा (माधारण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों के, जहाँ तक कि वे वर्तमान प्राप्तियों के अल्पर्गत हैं, छोड़कर) में प्रवर्तन जिनका मैमर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक श्रीयोगिक उपकरण एक पक्षकार है या जो उक्त श्रीयोगिक उपकरण को लागू हो मालूम है, ऐसी तारीख से एक वर्ष की प्रवधि के लिए निलमित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्ण उम्मेद के अधीन प्राप्त भूत सभी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यनाएं और वायित्व उक्त प्रवधि के लिए निलमित रहेंगे;

और उक्त आवेदन की प्रवधि समय-समय पर बढ़ा दी गई थी जिसमें से अग्रिम बढ़ाई गई प्रवधि 24 मई, 1982 तक के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए;

. और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आवेदन की प्रवधि 24 अगस्त, 1982 तक की और प्रवधि के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 अव की उपधारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) के छण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की प्रवधि 24 अगस्त, 1982 तक के लिए जिसमें वह सारी भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 3(17)/75-सीपूलस  
सी०क० मोदी, संयुक्त सचिव।

**S.O. 345(E)/18FB/IDRA/82.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order [other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amounts outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets] to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of the 24th May, 1982 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 24th August, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 24th August, 1982.

[File No. 3(17)/75-CUS]  
C. K. MODI, Jt. Secy.